points in all Central and State Government enforcement agencies have been established to promote inter-agency cooperation in enforcement work. BSF and Coast Guard, who are deployed on the land and Coastal border have been vested with the powers under the Customs Act to interdict narcotic drugs in addition to the Central and State Government enforcement agencies empowered under NDPS Act.

बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय निधियों को अन्य मदों पर खर्च किया जाना

5445. श्री जगन्नाईन आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को उपयोग में लाने में विफल रही है और इन निधियों का उपयोग उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों हेतु किया गया है, जिनके लिए उन्हें उपलब्ध कराया गया था, यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन मदों हेतु धन उपलब्ध कराया गया और प्रत्येक मद पर कितना धन खर्च किया गया तथा कितना धन अन्य मदों पर खर्च किया गया और क्या इस धन का अन्य मदों में स्थानांतरित किया जाना उचित था; और

(ख) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया है और लेखाओं को ठीक प्रकार से नहीं रखा गया है; यदि हाँ तो क्या केन्द्रीय सरकार वित्तीय अनियमितताओं और किये गये गोलमाल हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वीरप्पा मोइली) : (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता सकल ऋणों और सकल अनुदानों के रूप में समग्र योजना के लिए जारी की जाती है जिसका तात्पुक्त राज्य वार्षिक योजना के तहत किसी विशेष विकास मद तथा स्कीम से नहीं है। योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्ययों तथा राज्य वार्षिक योजना 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए स्वीकृत परिव्ययों के प्रति राज्य सरकार द्वारा बताए गए व्यय को दर्शाने वाले ब्यौरे अनुपत्र में दिए गये हैं। [देखिये परिशिष्ट------अनुपत्र सं० 112]

(ख) जहाँ तक बिहार सरकार द्वारा रखे जा रहे लेखों का सम्बन्ध है, यह उल्लेख किया जाता है कि यदि राज्य सरकार द्वारा राज्य वार्षिक योजना के सम्बन्ध में व्यय में कमी होने की जानकारी दी जाती है तो उस मामले में राज्य सरकार को देय सामान्य केन्द्रीय सहायता में से आनुपातिक कटौती कर दी जाती है। संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार किसी राज्य के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है, जो उन्हें राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने की व्यवस्था करता है। अतः यह राज्य विधान मंडल का कर्तव्य है कि यदि किसी राज्य में निधियों का सही उपयोग नहीं हो रहा है तो वह इस सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई करें।

मध्य प्रदेश में आबकार विभाग द्वारा मारे गये छापे

5446. श्री राघवजी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें आबकार विभाग द्वारा मारे गये छापों के दौरान लेखा पुस्तकों को जब्त किया गया था परन्तु उन्हें दस वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक लौटाया नहीं गया है; और

(ख) आबकार अधिनियम में लेखा पुस्तकों को रोके रखने की अवधि के संबंध में क्या प्रावधान है और उपर्युक्त मामलों में लेखा पुस्तकों को लौटाने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वीरप्पा मोइली) : (क) 88।

(ख) आबकार अधिनियम की धारा 132(8) के अंतर्गत, अधिकृत अधिकारी जब्त की गई लेखा पुस्तिकाओं को, जब्ती की तारीख से 180 दिन की अवधि तक अपने पास रख सकता है। इस अवधि के बाद आबकार अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों के पूरा होने की तारीख से अधिकतम 30 दिन की अवधि तक पुस्तिकाओं को आयुक्त अथवा मुख्य आबकार आयुक्त के अनुमोदन से रखा जा सकता है।

उपर्युक्त मामलों में पुस्तिकाएं रिलीज नहीं की गई हैं क्योंकि इन मामलों के संबंध में आबकार संबंधी कार्यवाहियां दण्ड, अपीलों तथा अभियोजनों सहित निर्णय की विभिन्न अवस्थाओं में पड़ी हैं।

Import duty on brass scrap

5447. SHRI CHIMANBHAI MEHTA :
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the import of scrap used by brass foundaries is duty free; if so, whether this scrap when used in casting and in moulding and the process generating scrap, is excisable;

(b) whether brass foundaries use recycled

scraps seven to twenty times which was tax free but is now excisable;

(c) whether it is a fact that finished product made out of this brass is not excisable;

(d) if so, how the recycled scrap, which is taxed, is eligible for Modvat;

(e) whether it is a fact that 400 foundries and 5000 brass factories employing 1 lakh people have closed down in Jamnagar city;

(f) whether it is also a fact that small factories have to approach 45—50 departments for revenue and other purpose;

(g) whether due to new tax on plastic waste processing, the price difference of the intermediates produced by small and big scale industries are almost nil or very much narrowed down; and

(h) whether the small waste processors produce low quality intermediates and would not stand against the competition of large scale, brand name companies, due to almost negligible or nil difference?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) no, sir. Import of scrap used by brass foundaries is not duty free.

(b) Prior to 1-3-94 brass scrap produced in a factory out of duty paid material was excisable but exempted from excise duty under Notification No. 172/84-CE, dated 1-8-84. This exemption has been withdrawn in the budget.

(c) and (d) No, Sir. All such products are excisable. However, for some goods like handicrafts, cycle valves etc., full exemption from excise duty has been extended. Excise duty, if any, paid on scrap is available as Modvat credit for payment of duty on dutiable products. Modvat rules do not allow any input credit when the finished product is exempted.

(e) Factories of Jamnagar had observed strike from 7th March, to 23rd March, 1994 in protest against the changes made in the budget. Now reportedly all the units are working.

(f) As far as central excise department is concerned, a small manufacturer has to give only one declaration in a year. Information about other departments is not available with Department of Revenue.

(g) The conditional full exemptions from excise duty to plastic waste scrap were withdrawn in the 1994-95 budget. The small scale units involved in such activities are in general, covered by the general small scale exemption scheme under which they pay either no duty or duty at concessional rates compared to that paid by the large scale units. It cannot be said therefore that the price differntial of intermediates between the big and small units has narrowed down due to the levy of duty alone.

(h) There should be a price difference in respect of intermediate goods produced by small units and big scale industries as small units are eligible for small scale benefits under Notification No. 1/93-CE. Small waste processors manufacture low quality goods and have their own specific market which is different from the market for high quality, high value goods manufactured by big scale brand name companies.

Investment offers from plantation firms

5448. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of the Central Government that many plantation firms have sprung up offering unbelievable returns in future to investments made at present; and

(b) what steps Central Government took or intend to take to protect the interests of the innocent investors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) The plantation investment schemes are floated by the companies with the approval of State Government concerned wherever required. At this juncture there is no monitoring mechanism in the Central Government on such investment offers by the plantation firms.

Private Sector Financial Institutions

5449. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR : Will the Minister of FINANCE be